



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 29, 2004/आश्विन 7, 1926

No. 226]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 29, 2004/ASVINA 7, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2004

जांच शुरुआत

(मध्यावधि समीक्षा)

विषय: यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित डी(-) पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लिसीन बेस (पीएचपीजी बेस) के भारत में आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबंधित मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत।

सं. 15/20/2004-डीजीएडी:- यतः 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियम कहा गया है) के अंतर्गत दिनांक 7 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 14/6/2002-डीजीएडी के द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने यूरोपीय संघ, इटली (जिसे एतदपश्चात संबद्ध देश/क्षेत्र कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित पीएचपीजी बेस (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए अपने अंतिम जांच परिणामों को अधिसूचित किया था।

और यतः दिनांक 1 मई, 2003 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं० 71/2003-सीमाशुल्क द्वारा संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

## 2. समीक्षा के लिए अनुरोध

और यतः नियमों में प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लगाए रखने की जरूरत की समय-समय पर समीक्षा किया जाना अपेक्षित है और यदि प्राधिकारी प्राप्त

निश्चयात्मक सूचना के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि इस प्रकार के शुल्क को निरंतर लगाए रखने का कोई औचित्य नहीं है तो प्राधिकारी केन्द्र सरकार को इसे वापस लेने की सिफारिश कर सकते हैं। उपरोक्त प्रावधान के होते हुए भी प्राधिकारी के लिए किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गयी समीक्षा की आवश्यकता की पुष्टि करने वाली निश्चयात्मक सूचना के आधार पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद एक उचित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या पाटन के प्रतिसंतुलन के लिए शुल्क को लगातार जारी रखना आवश्यक है, कि शुल्क की समाप्ति अथवा परिवर्तित अथवा दोनों कर दिए जाएं तो क्या क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार यूरोपीय संघ के एक निर्यातक अर्थात् मै0 रिकॉर्डती, इटली ने लागू पाटनरोधी शुल्क की परिवर्तित परिस्थितियों में मध्यावधि समीक्षा के लिए यूरोपीय संघ के जरिए अनुरोध किया है।

### 3. समीक्षा के लिए आधार

मूल जाँच की अवधि के दौरान ईयू से सम्बद्ध वस्तु के प्रमुख उत्पादकों और निर्यातकों में से एक मै0 रिकॉर्डती, इटली ने सूचित किया है कि उन्होंने दिसम्बर, 2002 से पीएचपीजी बेस का उत्पादन बंद कर दिया है। प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया है कि वर्ष 2002-03 के दौरान मूल जाँच की जाँच अवधि के दौरान सम्बद्ध वस्तु के केवल दो प्रमुख निर्यातक थे और मौजूदा समीक्षा के लिए आवेदक के अतिरिक्त दूसरे निर्यातक के लिए मूल जाँच के दौरान न्यूनतम पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। परिस्थितियों में इस परिवर्तन पर समीक्षा की शुरुआत करने के लिए उपयुक्त विचार किया गया है।

### 4. जाँच शुरुआत

परिवर्तित परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई निश्चयात्मक सूचना के मद्देनजर लागू उपाय की समीक्षा करना जरूरी हो जाने के कारण निर्दिष्ट प्राधिकारी उपरोक्त नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 की धारा 9क (5) के प्रावधान के अनुसार परिवर्तित परिस्थितियों के मद्देनजर पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करना उचित समझते हैं।

दिनांक 7 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं0 14/6/2002-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित अंतिम जाँच परिणामों की समीक्षा का निर्णय लेकर प्राधिकारी एतद्वारा नियमों के अनुसार जाँच आरम्भ करते हैं ताकि यह समीक्षा की जा सके कि क्या यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित पीएचपीजी बेस के आयातों पर शुल्क को लगातार लगाया जाना पाटन के प्रतिसंतुलन के लिए जरूरी है, शुल्क को समाप्त अथवा परिवर्तित अथवा दोनों कर दिए जाने से क्या क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

### 5. विचाराधीन उत्पाद

मूल जाँच और वर्तमान समीक्षा में शामिल उत्पाद डी (-) पैरा हाइड्राक्सी फिनाइल ग्लिसीन बेस (पीएचपीजी बेस) है जो उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम और आई टी सी एच एस वर्गीकरण की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के शीर्ष सं0 2942.00 के अंतर्गत

आता है। तथापि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार बाध्यकारी नहीं है।

## 6. प्रक्रिया

जांच द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि क्या पाटन की समाप्ति के लिए शुल्क को जारी रखा जाना आवश्यक है तथा क्या शुल्क के हटाए जाने अथवा उसमें परिवर्तन करने अथवा दोनों से क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

(i) समीक्षा में दिनांक 7 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं० 14/6/2002-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे।

(ii) इस समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004 की है। तथापि क्षति विश्लेषण की अवधि, वर्ष 2000-01 से वर्ष 2003-04 तक की होगी।

(iii) इस जांच में शामिल देश/क्षेत्र यूरोपीय संघ हैं।

(iv) उपर्युक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 तथा 20 के प्रावधान, आवश्यक परिवर्तनों सहित इस समीक्षा पर लागू होंगे।

## 7. सूचना देना

संबद्ध देशों/क्षेत्र के निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को अलग-अलग लिखा जा रहा है कि वे निर्धारित प्रपत्र में एवं तरीके से संगत सूचना प्रस्तुत करें एवं अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराएं :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी)

वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन

नई दिल्ली-110011

अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संबंधित अपने निवेदन निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय निवेदन करने वाले किसी पक्षकार द्वारा उसका अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, जिसे जांच के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण हेतु सार्वजनिक फाइल में रखा जाएगा।

**8. समय-सीमा**

वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना तथा सुनवाई हेतु किसी प्रकार के अनुरोध लिखित में भेजे जाने चाहिए जो उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुँच जाए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है, अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

**9. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं। यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है अथवा सूचना किसी भी रूप में अधूरी होती है तो प्राधिकारी, अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अभिजित सेनगुप्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2004

**Initiation Notification**

(Mid-term Review)

**Subject :** Initiation of Mid-term Review of anti-dumping duty imposed on imports into India of D(-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base (PHPG Base) originating in or exported from European Union.

**No. 15/20/2004-DGAD** - Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the Rules), vide Notification No. 14/6/2002-DGAD dated 7<sup>th</sup> March 2003, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) notified its final findings recommending definitive anti-dumping duty on import of PHPG Base (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from the European Union, Italy (hereinafter referred to as subject country/territory).

And Whereas definitive anti-dumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 71/2003-Customs dated 1<sup>st</sup> May 2003.

## 2. Request for Review

Whereas the Rules require the Authority to review, from time to time, the need for continued imposition of Anti-Dumping Duty and if it is satisfied, on the basis of positive information received by it that there is no justification for continued imposition of such duty, the authority may recommend to the Central Government for its withdrawal. Notwithstanding, the above provision, the authority is required to review, on the basis of positive information submitted by any interested party substantiating the need for a review, provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty, whether continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

In terms of the above provision, one of the major exporters from the European Union i.e. M/s. Recordati, Italy has filed a request, through the European Union, for a changed circumstances mid-term review of the anti-dumping duty in force.

## 3. Grounds for Review

One of the major producers and exporters of the subject goods from the EU during the period of original investigation M/s Recordati, Italy has informed that they have discontinued the production of the PHPG Base from December 2002. It is noted by the Authority that there were only two major exporters of the subject goods during the period of investigation of the original investigation during 2002-03 and another exporter besides the applicant for the current review had a de minimus dumping margin determined during the original investigation. This change in circumstances is considered appropriate to initiate a review.

## 4. Initiation

Having regard to the positive information provided by the applicant indicating the changed circumstances necessitating a review of the measure in force, the Designated Authority now considers that a mid-term review of the Anti-dumping Duty is appropriate in view of the changed circumstances, in terms of the provision of Section 9A(5) of the Customs Tariff (Amendment) Act 1995 read with Rule 23 surpa.

Having decided to review the final findings notified vide Notification No.14/6/2002-DGAD dated 7<sup>th</sup> March 2003, the Authority hereby initiates the investigations in terms of the Rules, to review whether continued imposition of the duty on imports of PHPG Base originating in or exported from the European Union is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

2944 G/104-2

## 5. Product under consideration

The product involved in the original investigation and the current review is D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base (PHPG Base) falling under heading No.2942.00 in Chapter 29 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act and ITC HS classification. This classification, however, is indicative only and, in no way, binding on the scope of the present investigation.

## 6. Procedure

The investigation will determine whether continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury is likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

- (i) The review will cover all aspects of Notification No.14/6/2002-DGAD dated 7<sup>th</sup> March 2003.
- (ii) The period of investigation for the purpose of this review will be 1<sup>st</sup> April 2003 to 31<sup>st</sup> March 2004. However, injury analysis shall cover the years from 2000-01 to 2003-04.
- (iii) The country/territory involved in this investigation are the European Union.
- (iv) The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Anti-Dumping Rules supra shall be *mutatis mutandis* applied in this review.

## 7. Submission of Information

The exporters in subject country/territory, their governments through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

The Designated Authority  
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties (DGAD)  
Ministry of Commerce & Industry  
Department of Commerce  
Udyog Bhavan  
New Delhi-110011  
Fax No.91-11-23014418

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making confidential submissions before the Authority is required to file a non-confidential version of the same, for placing the same in the public folder for inspection by all other interested parties to the investigation.

## **8. Time Limit**

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

## **9. Inspection of Public File**

In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the submissions made by other interested parties before the Designated Authority. In case an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may records its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ABHIJIT SENGUPTA, Designated Authority